

२१वाँ दीक्षांत समारोह, डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय
3 मई २०२३

असम के राज्यपाल एवं डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय के कुलाधिपति
महामहिम श्री गुलाब चन्द कटारिया
का
उद्घाटन भाषण

माननीय उपराष्ट्रपति और डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि महामहिम श्री जगदीप धनखड़ जी

माननीय मुख्यमंत्री श्री हिमन्त विश्व शर्मा जी

पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय और आयुष के माननीय केंद्रिय मंत्री श्री सर्वानन्द सोनोवाल जी

डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय के सम्मानित कुलपति प्रोफेसर जितेन हजारिका जी
कुलसचिव

समस्त विभागों के अधिष्ठातागण

आज के समारोह में डी.एससी. (D.Sc.) एवं डी.लिट. (D.Litt.) (मानद उपाधि) से सम्मानित होने वाली विभिन्न विभूतियाँ

विश्वविद्यालय के अन्य प्रतिष्ठित अतिथिगण, विश्वविद्यालय के समस्त विद्वत प्राचार्य, उपाचार्य एवं आचार्यगण एवं प्रशासकीय सहायक, समस्त अभिभावकगण, समस्त छात्र-छात्राएँ, देवियों एवं सज्जनों

आज डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय के इक्कीसवें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है।

डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र का दूसरा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय स्थापना के बाद से इस क्षेत्र का शैक्षणिक विकास करने और उच्चतम मानक के अनुसंधान का संचालन करने के 57 गौरवशाली वर्ष पूरे कर चुका है। 1965 में स्थापित डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय अध्ययन के सभी क्षेत्रों में उच्च शिक्षा और अनुसंधान का प्रसार करने में अग्रणी रहा है, जिसने विद्यार्थियों के जीवन को समृद्ध आकार दिया है। डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय ने क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने के साथ-साथ क्षेत्र के समृद्ध पारंपरिक क्षेत्रीय ज्ञान एवं कौशल को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट योगदान दिया है।

आज डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय अपने इक्कीसवें दीक्षांत समारोह का जश्न मना रहा है। मैं प्रत्येक स्नातक को बधाई देता हूँ, जिन्होंने यह उपाधि प्राप्त करने के लिए कठोर श्रम किया है। दीक्षांत समारोह शिक्षकों और संस्थान के अन्य हितधारकों के निःस्वार्थ सेवाभाव के साथ-साथ छात्रों की वर्ष पर्यन्त कड़ी मेहनत और समर्पण का जश्न मनाने का अवसर है। मैं भविष्य में विद्यार्थियों की सफलता की कामना करता हूँ।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि साक्षरता अपने आप में कोई शिक्षा नहीं है। साक्षरता शिक्षा का न ही अंत है, और न ही प्रारंभ है। शिक्षा से मेरा अभिप्राय शिशु एवं मनुष्य के सर्वश्रेष्ठ सर्वांगीण शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक उत्कर्ष से है। 21वीं सदी में भी शिक्षा का सार संपूर्ण मानव जाति में सम्यक् दृष्टि एवं सम्यक् विकास अर्जित करना बना रहेगा।

आज हम भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष मना रहे हैं, यह समय है कि हम भविष्य के लिए एक विस्तृत शैक्षणिक दृष्टिकोण (रोडमैप) तैयार करें। यह आवश्यक है कि हम उन मामलों पर गहराई से आत्मनिरीक्षण करें, जो एक राष्ट्र के रूप में हमारी चिंता करते हैं और हमारी प्राथमिकताओं का पुनर्मूल्यांकन करते हैं। हमें ऐसे तरीके खोजने की जरूरत है, जिससे हम खुद को आत्मनिर्भर बना सकें। यह समय है कि हम में से प्रत्येक राष्ट्र की उन्नति के लिए काम करने का संकल्प लें। इस संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन सही दिशा में उठाया गया एक अहम कदम है। यह प्राथमिक विद्यालय स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तक 21वीं सदी के शिक्षार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए पाठ्यक्रम का बहुत आवश्यक सोपान है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षा में प्रमुख सुधारों पर केंद्रित है, जो अगली पीढ़ी को नए डिजिटल युग में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाएगी। नई शिक्षा नीति व्यापक रूप से भारत की नई शिक्षा प्रणाली के दृष्टिकोण को रेखांकित करती है और प्राचीन उच्च आदर्शों का संवर्धन करने की प्रेरणा भी देती है।

नई शिक्षा नीति सतत अधिगम के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु पाँच मुख्य स्तम्भों पर ध्यान केंद्रित करती है, जो कि "सामर्थ्य", "अधिगम्यता", "गुणवत्ता", "साम्यता" एवं "उत्तरदायित्व" हैं। इसे नागरिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार (डिजाइन) किया गया है, क्योंकि समाज और अर्थव्यवस्था में ज्ञान की मांग के लिए नियमित आधार पर नए कौशल की आवश्यकता होती है। नई शिक्षा नीति गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसर पैदा करने पर ज़ोर देती है, जिससे **संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 2030** में सूचीबद्ध सम्पूर्ण रोज़गार, उत्पादकपूर्ण रोजगार और गरिमापूर्ण श्रम के लक्ष्य को हासिल किया जा सके।

यह खुशी की बात है कि डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय और उसके संबद्ध कॉलेजों के लिए चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम की शुरुआत के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए पाठ्यक्रम पहले ही तैयार किया जा चुका है, और इसे अकादमिक परिषद द्वारा अनुमोदित भी किया जा चुका है। हाल ही में वैश्विक मंच पर विश्वविद्यालय को और अधिक विश्वसनीयता मिली है। जबकि डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय **जी 20 विश्वविद्यालय कनेक्ट कार्यक्रम** की मेजबानी और भाग लेने के लिए देश के उच्च शिक्षा के चुनिंदा 76 संस्थानों में से एक था, जिसका आदर्श वाक्य "**एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य**" है। जो हमारे भारतीय मूल्यों और परंपराओं के अनुरूप **वसुधैव कुटुंबकम्** की भावना को आत्मसात् करता है।

नई शिक्षा नीति 2020 शिक्षार्थियों के बीच न केवल विचार में, बल्कि भावना, बुद्धि और कर्मों में भी भारतीय होने के साथ-साथ ज्ञान, कौशल, मूल्य और स्वभाव को विकसित करने के लिए एक आंतरिक गर्व की अनुभूति कराती है। प्राचीन भारत में शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान का अर्जन ही नहीं था, बल्कि स्वयं की पूर्ण अनुभूति और मुक्ति भी केंद्र में थी। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी जैसे प्राचीन भारत के विश्वस्तरीय संस्थानों ने विविध विधाओं एवम् विषयों में शिक्षण और अनुसंधान के उच्चतम मानकों को स्थापित किया और दुनिया भर के विद्वानों और छात्रों की मेजबानी की। यह महत्वपूर्ण है कि हम इस परंपरा और विरासत का सम्मान करें और इसके प्रचार-प्रसार की दिशा में काम करें। मुझे आपको यह सूचित करते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय ने भारतीय ज्ञान प्रणाली के ढांचे पर भारत की शिक्षा प्रणाली को पुनःस्थापित करने के उद्देश्य से **भारतीय ज्ञान प्रणाली केंद्र (सीआईकेएस)** की स्थापना की है।

यह उचित समय है कि कौशल आधारित शिक्षा को प्राथमिकता और महत्व दिया जाए। विशेष कौशल के अधिग्रहण से कार्यस्थलों पर सहभागिता बढ़ेगी एवं कार्य सुचारू रूप से चलेंगे। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण संभावना यह है कि यह युवाओं के बीच उद्यमिता की भावना को बढ़ावा दे सकता है। रोजगार सृजन करने के रूप में एक राज्य क्या सुनिश्चित कर सकता है, इसकी अपनी एक सीमा है। आप सभी की तरह उद्यमी, गतिशील, आत्मविश्वासी और कुशल युवाओं को उद्यमियों के रूप में आगे आना चाहिए, जिससे दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा हों। यह खुशी की बात है कि डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय अपने छात्रों को कौशल-आधारित शिक्षा विकसित करने पर बहुत प्राथमिकता दे रहा है।

यह जानकर खुशी हुई कि विश्वविद्यालय के भीतर कई छात्र स्टार्ट-अप परिचालन में संलग्न हैं, और ये देश के विभिन्न हिस्सों और यहां तक कि बाहर से ग्राहकों को आकर्षित करने में सफल रहे हैं। अधिगम कौशल का मूल्य यहां साबित होता है। इन छात्रों को कभी भी कहीं और नौकरी नहीं तलाशनी पड़ेगी; बल्कि वे अन्य लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं। इसलिए, उद्यमितापूर्ण उद्देश्य के लिए कौशल का अर्जन समय की परम आवश्यकता है। विशेष रूप से गरीब, कमजोर, वंचित वर्गों के सन्दर्भ में सामाजिक समावेशिता का मुद्दा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर भारत को विकास करना है तो यह गरीबों की कीमत पर नहीं हो सकता। अब तक, हाशिए पर पड़े वर्गों को उच्च शिक्षा दिलाने के कार्य में बहुत कुछ हासिल नहीं किया गया है। एक शैक्षिक प्रक्रिया के लाभ, जो उन्हें रोजगार के अवसरों को सुरक्षित करने के साथ-साथ सामाजिक और आर्थिक गतिशीलता के लिए अवसर प्रदान करने में सक्षम बनाएंगे। यह उनका मूल अधिकार है, जो कि उन्हें मिलना ही चाहिए।

इसके पश्चात लड़कियों को उच्च शिक्षा में शामिल करने की बात आती है। यह एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि हर जगह लैंगिक भेदभाव व्याप्त है। परंतु यह बड़े गर्व की बात है कि डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय को इस तरह के भेदभावपूर्ण प्रथाओं से मुक्त घोषित करा जा सकता है। क्योंकि इस विश्वविद्यालय में 60% से अधिक छात्राएँ शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। हमारे उच्च शिक्षा संस्थानों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए ताकि उन्हें समय की जरूरतों के प्रति अधिक प्रासंगिक और संवेदनशील बनाया जा सके और लैंगिक समानता और सशक्तिकरण भी सुनिश्चित किया जा सके। उच्च शिक्षा संस्थानों को डायन (विचहंटिंग), दहेज जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ाई में भी अग्रणी होना चाहिए।

हमें विशिष्ट समस्याओं के निवारण हेतु सार्थक एवं विस्तारपूर्ण गतिविधियों के साथ पारंपरिक कक्षाओं को एकीकृत करने और उनमें नई एवं आधुनिक विधाओं को अंगीकृत करने की भी आवश्यकता है।

एक और बड़ा संकट पर्यावरण का संकट है। उच्च शिक्षा संस्थानों को पर्यावरण सुरक्षा को बढ़ावा देने में प्रकाशस्तंभ के रूप में कार्य करना चाहिए। छात्रों में पर्यावरण के प्रति सम्मान पैदा किया जाना चाहिए। प्रकृति के प्रति सम्मान, प्रकृति से सीखना और प्रकृति के साथ जुड़ाव शिक्षा के हर स्तर पर हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए। एक हरित, कागजरहित कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का दोहन महत्वपूर्ण है। यहां भी डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय पीछे नहीं है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के डिजिटल इंडिया मिशन की सही मायने में वकालत करते हुए, ऑनलाइन प्रवेश, ऑनलाइन शुल्क जमा करने आदि जैसी कई डिजिटल पहल की गई हैं।

क्षेत्रीय एवं जनजातीय संस्कृति, स्थानीय भाषाओं और उनके प्रचार के लिए सम्मानजनक एवं विभिन्न स्तर पर पहल होनी चाहिए, जिस पर विश्वविद्यालयों को ध्यान देना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अंग्रेजी महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारी अपनी भाषाओं और बोलियों को जीवंत और कार्यात्मक बनाना आज हमारे विश्वविद्यालयों में शिक्षा की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। यहां तक कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने क्षेत्रीय भाषाओं और विदेशी भाषाओं सहित अपनी मातृभाषा के महत्व पर जोर दिया है। हाल ही में डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय द्वारा बोड़ो, मिसिंग, देउरी और कोरियाई भाषा में पाठ्यक्रम खोलने का निर्णय प्रशंसनीय है।

अंत में, मैं सभी छात्रों को उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप अपने पूरे जीवन में ज्ञान प्राप्त करने की अपनी जिजिविषा जारी रखेंगे और अपने सह-प्राणियों और अपने समाज की सेवा करने के लिए प्राप्त ज्ञान का उपयोग अवश्य करेंगे। यहां मैं महात्मा गांधी जी के एक उद्धरण के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि शिक्षा में ऐसी क्रांति लाई जानी चाहिए कि एक साम्राज्यवादी शोषणकर्ता की जरूरतों को पूरा करने के बजाय अति गरीब ग्रामीण की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। यह युवा ही हैं जिन पर राष्ट्र निर्भर करता है और उनका कार्य, नैतिकता, समर्पण और देश की सेवा करने की प्रतिबद्धता ही भारत की सबसे बड़ी ताकत है।

इन्हीं विचारों के साथ मैं औपचारिक रूप से डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय के इक्कीसवें दीक्षांत समारोह का उद्घाटन करता हूँ और एक बार फिर उन सभी छात्रों को बधाई देता हूँ, जिन्हें आज उपाधि प्रदान की जा रही है और उनके जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की कामना करता हूँ।

धन्यवाद!

जय हिन्द